कपड़ा-उत्पादन

3560. **श्री अजीत जोगी:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1991-92 के दौरान कपड़ा-उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कपड़ा-उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) पिछले अनेक वर्षों से कपड़े का उत्पादन बढ़ रहा है। वर्ष 1991-92 के दौरान यह लगभग उतना ही था जितना कि पिछले वर्ष में था।

(ग) और (घ) सरकार ने कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाए किए हैं। इन में से कुछ उपाय हैं:

(1) नई औद्योगिक नीति में स्थान सम्बन्धी प्रतिबन्ध को छोड़ करके मिल/विकेन्द्रीकृत विद्युत-करघा स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) वस्त्र मशीनों का आयात किया जा सकता है तथा ऐसी मशीनों पर शुल्क को पहले से कम कर दिया गया है।

(3) वर्ष 1986 में वस्त्र आधुनिकीकरण निधि का सृजन किया गया था तथा अगस्त, 1992 के अन्त तक 397 मामलों में 1367 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 306 आवेदन-पत्रों पर 853 करोड़ रु० की राशि वितरित कर दी गई है।

(4) गिनिंग और प्रोसेसिंग एककों का आधुनिकीकरण।

घाटे में चलने वाली कपड़ा मिलों को अपनी भूमि बेचने की अनुमति

3561. **श्री छोटूभाई पटेल:** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रही कपड़ा मिलों के अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अपनी भूमि बेचने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलें कौन-कौन सी हैं और किन-किन मिलों ने अब तक अपनी भूमि बेच दी है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० को फालतू भूमि बेचने की अनुमति नहीं है। निजी वस्त्र मिलों के संबंध में अनुमति सम्बद्ध केन्द्रीय और राज्य सरकारों के नियमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त करनी होती है।

Indo-EEC Textiles agreement

3562. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the European Economic Community pressed for an almost flat rollover of the agreement during the negotiations held recently between India and EEC at Brussels over the Indo-EEC textiles agreement;

(b) if so, what is Government's reaction thereto;

(c) whether Government have achieved any success in negotiating for higher growth rates for all categories under quota and for increased flexibility; and

(d) if so, the final outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Negotiations for renewal of the current Indo-EEC Textile Agreement have not yet been concluded. The Government will continue thier efforts to secure inprovements in the Agreement including higher growth rates and increased flexibilities.

Modernisation of Hosiery Industry

3563. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government propose to take any steps to modernise the Hosiery Industry with a view to catering to the